साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every...

वर्ष : 10, अंक : 43 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 28 मई 2025 से 3 जून 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

10 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो जाएगा कम, करना होगा यह काम

नई दिल्ली। एक नए अध्ययन में कहा गया है कि दुनिया भर में खासकर उत्तरी अमेरिका और उप-सहारा अफ्रीका में लोगों को कम कार्बन वाली जीवनशैली अपनाने से जलवायु में बदलाव को कम किया जा सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि धरती को गर्म करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का दुनिया भर में घरेलू उत्सर्जन में दो से पांचवें हिस्से तक की कटौती करने में मदद मिल सकती है।

शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने 21 कार्बन को कम करने वाली कार्रवाइयों की पहचान की है, जिन्हें यदि दुनिया भर के उत्सर्जकों के शीर्ष 23.7 फीसदी द्वारा अपनाया जाता है, तो वैश्विक कार्बन पदचिह्नों को 10.4 गीगाटन सीओ2 के बराबर तक कम किया जा सकता है। शोध में 116 देशों में घरेलू उपभोग पर आधारित उत्सर्जन का लगभग 40.1 फीसदी का विश्लेषण किया गया। कार्बन के स्तर को कम करने के लिए घर जो कदम उठा सकते हैं, उनमें व्यावसायिक सेवाओं के उपयोग में कमी लाने से कार्बन उत्सर्जन में लगभग 10.9 फीसदी की कमी आएगी। स्वस्थ शाकाहारी आहार की ओर बढ़ना, पशु-आधारित भोजन, चीनी और अस्वास्थ्यकर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की खपत में कमी लाने से उत्सर्जन में 8.3 फीसदी की कमी आ सकती है।

ऊर्जा-कुशल भवन मानकों को लागू करना जिनसे उत्सर्जन में छह फीसदी की कमी आने की संभावना है। निजी वाहनों से सार्वजनिक यातायात के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में 3.6 फीसदी की कमी आ सकती है। घरेलू उपकरणों को साझा करना और उनकी मरम्मत करने से तीन फीसदी की कमी आने की संभावना है। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित शोध में शोधकर्ताओं ने बताया कि यातायात या गतिशीलता और सेवाओं से संबंधित उपभोग पैटर्न में बदलाव करने से 11.8 फीसदी और 10.2 फीसदी उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी अमेरिका में कार्बन उत्सर्जन में कमी की पर्याप्त संभावना है, जबकि कुछ उप-सहारा अफ्रीकी देश - जैसे मॉरीशस, नामीबिया और चाड में भी जलवायु में बदलाव को कम करने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। यातायात और सेवाओं से संबंधित उपभोग पैटर्न में बदलाव करने से 11.8 फीसदी और 10.2 फीसदी उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। अध्ययन से पता चलता है कि कम कार्बन वाली जीवनशैली अपनाना जलवायु परिवर्तन को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अधिक उत्सर्जन वाले घरों को चुन करके, कार्बन में भारी कटौती हासिल की जा सकती है और अपने वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के करीब पहुंचा जा सकता है। शोधकर्ताओं ने दो डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के लिए आवश्यक वैश्विक प्रति-व्यक्ति औसत से अधिक घरों को चुनते हुए घरेलू खर्च के आंकड़ों का विश्लेषण किया, अलग-अलग कम कार्बन वाले कामों की कार्बन कमी क्षमता का व्यापक विश्लेषण प्रदान किया। शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि जलवायु में बदलाव को कम करने के लिए उपभोग-आधारित कम कार्बन रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है। शोध के निष्कर्ष जलवायु परिवर्तन से निपटने में उपभोक्ताओं को शामिल करने के महत्व को सामने लाते हैं, जो बहुत ज्यादा उत्सर्जकों को चुनने वाले न्यायसंगत उपायों को उजागर करते हैं। यह शोध कार्बन पदचिह्नों को कम करने के लिए जीवनशैली में बदलाव की क्षमता के बारे में अहम जानकारी प्रदान करता है। नीति निर्माताओं के लिए इन निष्कर्षों पर विचार करना और ऐसी रणनीतियों को लागू करना जरूरी है जो टिकाऊ उपभोग पैटर्न को प्रोत्साहित करती हैं।

मन की बात कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक चेतना जागृत करने का अनुपम प्रयास- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नई दिल्ली में मन की बात के 122वें संस्करण का किया श्रवण

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रवासियों से निरंतर संवाद के माध्यम मन की बात के 122वें संस्करण का नई दिल्ली प्रवास के दौरान श्रवण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मन की बात कार्यक्रम का श्रवण करने के बाद अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम जन संवाद का अनूठा माध्यम है। यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण की दिशा में सामूहिक चेतना जागृत करने का अनुपम प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम युवा शक्ति, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार से लेकर समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने वाला संवाद कार्यक्रम है, जो राष्ट्रवासियों को नई ऊर्जा और दिशा देता है। प्रधानमंत्री के ओजस्वी, प्रेरणादायक और दूरदर्शी विचार राष्ट्रसेवा, सामाजिक जागरूकता और जनहित में कार्य करने की सतत प्रेरणा देते रहते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात में बताया कि पिछले वर्षों में मधुमक्खी पालन क्षेत्र में भारत में एक क्रांति हुई है। आज से 10-11 साल पहले भारत में वार्षिक शहद उत्पादन 70-75 हजार मीट्रिक टन होता था। आज यह बढ़कर करीब सवा लाख मीट्रिक टन के आसपास हो गया है। इस तरह शहद उत्पादन में करीब 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के हजारों कार्य हुए प्रारंभ

इंदौर (नगर प्रतिनिधि) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा पर प्रारंभ हुआ जल गंगा संवर्धन अभियान का इंदौर जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह अभियान इंदौर जिले में व्यापक जनभागीदारी से जन-आंदोलन बन गया है। जिले में जल संग्रहण, जल संरक्षण और संवर्धन के हजारों कार्य प्रारंभ हो गये है। अभियान के तहत जहां एक और पूराने कुएं , बावड़ी और तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। वहीं दूसरी और नए तालाब बनाने का कार्य भी हाथ में लिया गया है। जिले में खेत-खेत में भी तालाब बनाये जा रहे है। वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य भी बड़े स्तर पर शुरू किया गया है।

कलेक्टर श्री आशीष ?सिंह ने निर्देश दिये कि अभियान को और अधिक गति प्रदान की जाये। शत-प्रतिशत लक्ष्य अगले चार दिन में पूरे कर लिये जायें। अभियान को प्रभावी बनाने में किसी भी तरह की कसर नहीं रखी जाये। यह अभियान राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आम-जन-जीवन से जुड़ा बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान है। सभी अधिकारी इस अभियान को पूर्ण गंभीरता क्रियान्वित करें। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज एआईसीटीएसएल के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में इस अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने विकाखंडवार अभियान की प्रगति की समीक्षा की। बताया गया कि यह अभियान इन्दौर जिले में जन आन्दोलन के रूप में ख्याति प्राप्त कर रहा है। ग्रामीणों और समाजसेवियों की भागीदारी से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों के फलस्वरूप इन्दौर में जल संचय होगा, जिसका सीधा लाभ आमजन और किसानों को मिलेगा। इसके लिए अभियान के तहत इंदौर जिले में जल संरक्षण और संवर्धन के हजारों कार्य प्रारंभ किये गए हैं। समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान इन्दौर में ख्याति प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में इन्दौर जिले में जल गंगा अभियान के अन्तर्गत 705 खेत तालाब, 1200 डग वेल रिचार्ज, 63 बावड़ी एवं चेकडेम जीर्णोद्धार, 5000 रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के साथ 12 अमृत सरोवर पर कार्य हो रहा है, जिसमें अधिकांश कार्य शुरू होकर प्रगति पर है। पिछले वर्ष 2024 में जिले में 101 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया इस बार लक्ष्य बढ़ाकर कार्य किया जा रहा है। इन्दौर जिले के 43 ग्राम पंचायतों में तालाबों का गहरीकरण कार्य किया जा रहा जिससे 2300 कृषकों को लाभ हुआ। मनरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक हितग्राही मूलक वृक्षारोपण किये गए जिसमें इन्दौर जिले में 3 लाख से अधिक पौधे रोपित किये गए और आने वाले समय में इस वर्ष 10 लाख पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है।

भूगर्भ जल का दोहन

भविष्य में सरकार, हमें और सब को यह सोचना होगा कि भूगर्भ जल को कैसे बचाया जा सके। इसका एक ही उपाय है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, लेकिन सिर्फ रेनवाटर हार्वेस्टिंग से नहीं होगा।

इंडस्ट्री जो बड़े पैमाने में पानी निकाल रही है, उसको नीति बनानी होगी। जिससे कि वहां के आसपास के लोगों को दिक्कत नहीं हो, खेती करने में दिक्कत नहीं हो और उनका भी काम हो। हम लोग चाहते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को लेकर जल्द से जल्द ऐसी नीति बने की भूगर्भ जल कैसे बचे।

विधायक रहे राजेन्द्र राजन का कहना है कि बेगूसराय इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में पेप्सी का प्लांट लगा और अब लगेगा कैम्पा कोला प्लांट। बेगूसराय जिला का जलस्तर पाताल मुखी है। यानी यहां की धरती पानी देने की क्षमता तेजी से खो रही है। साधारण बोरिंग कराने पर वर्षों से पानी नहीं निकलता है ।

बिहार के बेगूसराय की बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट आथोरिटी (बियाडा) क्षेत्र के आठ दस किलोमीटर के दायरे में पिछले तीन वर्षों के दौरान भूगर्भ जल का स्तर 20 से 30 फीट तक गिर गया है। ऐसा पेप्सी कंपनी के बाटलिंग प्लांट के कारण हो रहा है। भूगर्भ शास्त्री और स्थानीय नागरिकों का भी यही मानना है। यहां हर दिन 12 लाख लीटर पानी निकाला जा रहा है। इस कारण इस इलाके का जलस्तर लगातार गिर रहा है। कहते हैं प्लांट में मोटे मोटे आठ बोरिंग हुए थे, जिसमें दो ने पिछले साल से ही काम करना बंद दिया है। भूजल के लगातार दोहन से जल स्तर लगातार गिर रहा है। तीन साल पहले 15 से 20 फीट पर जल स्तर था, अब यह 40 से 50 फीट है। बोरिंग ने काम करना बंद कर दिया है और चापानल से भी कम पानी आ रहा है। आस पास के एक दर्जन गांवों के तीस से चालीस हजार लोग इस फैक्टरी का विरोध कर रहे हैं। अब तो जल भी दूषित हो गया है और पानी बदबू में भी आ रहा है। लोग चाहते हैं कि प्लांट बंद हो जाए या प्लांट अपने लिए दूसरी व्यवस्था करे। लोगों का कहना है कि पानी से बदबू भी आने लगा है।इसी बीच यह खबर है कि बेगूसराय में कैम्पा कोला की यूनिट बेगूसराय जिले के ग्रोथ सेंटर में स्थापित की जाएगी।इस परियोजना में कंपनी 1200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और यहां सॉफ्ट ड्रिंक्स का उत्पादन किया जाएगा। दावा यह किया जा रहा है कि बिहार में रिलायंस ग्रुप की पहली औद्योगिक यूनिट होगी, जो राज्य के औद्योगीकरण में एक नई दिशा तय करेगी।लोगों का कहना है कि पेप्सी प्लांट का सोशल ऑडिट होना चाहिए कि बेगूसराय के भू जल का करोड़ो लीटर उपयोग करने के बाद इस प्लांट से बेगूसराय के कितने बच्चों को रोजगार मिल रहा है द्य उसमें बेगूसराय की भागीदारी निश्चित होनी चाहिए उसके बाद ही केम्पा कोला को प्लांट लगाने की अनुमानित मिलनी चाहिए द्य जमीन जाए बेगूसराय का प्रदूषण झेले बेगूसराय रोजगार पाए सिर्फ बाहरी गांव वाले लगातार गिरते भू-जल स्तर की शिकायत लेकर स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह के पास पहुंच रहे हैं । इसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, देखिए यहां के जनमानस, यहां के किसान, यहां के निवासी, चार साल हुआ है, पेप्सी का प्लांट जब से खुला है। अभी यहां गांव के किसान लोग हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं। पेप्सी के प्लांट के कारण जो भूजल स्तर गिरा है इससे सभी को कठिनाई हो रही है। पानी पीने में कठिनाई हो रही है साथ ही किसान को भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पेप्सी के प्लांट को लेकर अपना विरोध जताया है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्लांट का उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि पेप्सी गंगा से जल लेकर अपना उत्पादन करेगा और पानी हार्वेस्ट किया जाएगा, लेकिन न तो वो गंगा से जल ले रहे हैं और न ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। प्लांट बंद करना होगा। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अप्रैल 2022 को इस प्लांट का उद्घाटन किया था। लोगों को लगा था कि बेगूसराय का विकास होगा, लेकिन उद्घाटन के 3 साल बाद ही लोग चाह रहे कि प्लांट बंद हो जाए। जल स्तर में यह कमी सिर्फ पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट वरुण बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के आसपास ही नहीं, बल्कि असुरारी, बथौली, मालती, पपरौर, हवासपुर, बीहट से लेकर पकठौल तक के गांव में हो गई है। लोग परेशान हैं, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा है। पिछले डेढ़ साल से आंदोलन जारी है। जब स्थानीय लोगों की बात किसी ने नहीं सुनी तो व्यापक पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। बेगूसराय स्थित बियाडा बरौनी की 55 एकड़ की जमीन पर है यह प्लांट। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे प्रियम रंजन ने बताया कि 2022 में यहां पेप्सी प्लांट लगा। जब से प्लांट लगा है, जल संकट शुरू हो गया है। सिंचाई तक आफत हो गई है। जिस प्लांट को दक्षिण भारत, यूपी के हरदोई, बिहार के हाजीपुर से भगाया गया, हाजीपुर में अभी भी पानी की समस्या बरकरार है, उस प्लांट को हमारे माथे पर थोप दिया गया। हम लोग ऐसे ही पानी से जूझ रहे हैं। बेगूसराय वाले पहले ही दुनिया के प्रदूषित शहरों में है। एक पानी बचा था, उसकी भी स्थिति गड़बड़ा रही है। पानी में आयरन सहित ऐसे कई केमिकल मिल रहे हैं जो शरीर, त्वचा और जीवन के लिए हानिकारक हैं। पेप्सी से रोजगार तो मिला नहीं, ऊपर से हम लोग जल संकट झेल रहे हैं। तालाब सूखा है, हमारा पानी ही निकाल कर पूरी दुनिया को पहुंचाया जा रहा है। यह उत्तर भारत का सबसे अधिक क्षमता का बॉटलिंग प्लांट है। बीहट निवासी रंजना सिंह का कहना है कि पहले जलस्तर अच्छा था। हम लोग पानी से धनी थे, लेकिन जब से पेप्सी प्लांट लगा है, तब से पानी का दोहन हो रहा है।

शहरी जलापूर्ति व्यवस्था

ह र साल गर्मी में जल संकट देखने को मिलता है। दिल्ली और गुरुग्राम हो या बेंगलूरु, पुणे जैसे शहर, सभी जगह पानी की आपूर्ति में कटौती, मात्रा निर्धारण और निजी टैंकरों से आपूर्ति की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। पिछले साल के जल संकट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली ने उच्चतम मांग वाले महीनों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना (समर एक्शन प्लान) शुरू की है। लेकिन पानी की किल्लत अब मौसमी आश्चर्य नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ते शहरों के लिए एक स्थायी चुनौती बन गई है, जो तत्काल और व्यवस्थागत सुधारों की मांग करती है। शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में दीर्घकालिक लचीलापन लाने में ये चार दृष्टिकोण मदद कर सकते हैं। सबसे पहले सीवेज को प्रदूषण स्रोत की जगह संसाधन में बदलने पर नए सिरे से विचार करना होगा। भारतीय शहरों में सप्लाई होने वाला लगभग 80 प्रतिशत पानी घरों की रसोई, शौचालयों और धुलाई जैसे कार्यों में इस्तेमाल होकर सीवेज के रूप में बाहर आ जाता है। हमारे आकलन के अनुसार 2030 तक भारतीय शहर प्रतिवर्ष 30 अरब घन मीटर से ज्यादा घरेलू सीवेज (डोमेस्टिक यूज्ड वाटर) उत्पादित करेंगे, जो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक होगा। शहरी निकाय इस पानी के शोधन और पुर्नउपयोग (ट्रीटमेंट और रियूज) के जरिए ताजे पानी की मांग को काफी हद तक घटा सकते हैं और इससे प्रदूषित होने वाले जल स्रोतों की सेहत भी सुधार सकते हैं। शोधित जल को पार्कों की सिंचाई और शहरी सीमाओं पर खेती, निर्माण कार्य व औद्योगिक गतिविधियां, ग्राउंड वॉटर रिचार्ज और सड़कों की सफाई जैसे गैर-पेयजल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बावजूद, जिन शहरों में वाटर ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहां भी इसके पुर्नउपयोग की दर सीमित है। शोधित प्रयुक्त जल के पुर्नउपयोग की दर सीमित होने का एक मुख्य कारण शहरी जल संसाधन योजना में इसके पुर्नउपयोग की रणनीति का व्यवस्थित रूप से शामिल नहीं होना है। इसके समाधान करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को शोधित प्रयुक्त जल के पुर्नउपयोग के लिए दीर्घकालिक, शहर-स्तरीय योजनाएं बनाने की जरूरत है। इनमें पानी की कमी का आकलन करने के लिए एक व्यापक जल संतुलन शामिल करना चाहिए, प्रयुक्त जल शोधन (यूज्ड वॉटर ट्रीटमेंट) और उसके पुर्नउपयोग (रियूज) के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करने चाहिए, वर्तमान और भविष्य में पानी की मांग के साथ-साथ शहरी विकास को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस साल की शुरुआत में ठाणे नगर निगम ने भारत की पहली ऐसी योजना को अपनाकर एक मिसाल कायम की है।

दूसरा, अर्बन ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। अक्सर नदियों के बाढ़ के मैदान, झील, प्राकृतिक नालों, पार्कों और जंगलों जैसे प्राकृतिक ब्लू-ग्रीन जगहों की कीमत पर भारतीय शहरों का त्वरित विस्तार होता है। दिल्ली ने पिछले 30 वर्षों में अपने लगभग आधे वेटलैंड्स खो दिए हैं, जबकि कंक्रीटीकरण के कारण बेंगलूरु अपने लगभग 40 प्रतिशत जल निकायों को खो चुका है। इसके कारण प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था को हुए नुकसान और पृथक सीवेज नेटवर्क के अभाव ने हमारे शहरों के सामने मानसून के दौरान बाढ़ और गर्मियों के समय भीषण गर्मी से प्रभावित होने का जोखिम बढ़ा दिया है, जो जल उपलब्धता को और भी मुश्किल बना रहा है। शहरी नियोजन (अर्बन प्लानिंग) में प्रकृति को नए सिरे से जोड़ना होगा। दिल्ली का 2041 मास्टर प्लान इसका उदाहरण देता है। इसकी ब्लू-ग्रीन पॉलिसी नालों की सफाई, ग्रीन बफर के निर्माण, वर्षा उद्यानों के विकास, छिद्रित फुटपाथ बनाने, ताकि बारिश का पानी जमीन के अंदर जा सके और इन स्थानों को पैदल व साइकिल मार्गों से जोड़ने जैसे कदमों के जरिए ब्लू-ग्रीन स्थानों को बढ़ाने का प्रयास करती है। ऐसा बुनियादी ढांचा एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करता है, जो तूफानी बारिश का पानी सोख लेता है, अर्बन हीट आइलैंड को कम करता है, और ग्राउंड वॉटर रिचार्ज को सुधारता है। तीसरा, पानी की कीमत तय करनी चाहिए, ताकि इसकी अहमियत पता चल सके। भारतीय शहरों में पानी पर बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती है। भले ही इसके पीछे की सोच अच्छी है, लेकिन ऐसी नीतियां जलापूर्ति करने वाले संस्थानों पर दबाव डालती हैं, जो मौजूदा जलापूर्ति व्यवस्था को सही से संचालित करने की योग्यता और उसे जारी रखने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह निजी निवेश को भी हतोत्साहित करता है और बुनियादी ढांचे को अक्षम बनाता है। आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए लक्षित सब्सिडी के साथ, पानी की कीमत तय करने के सुधार को लागू करना चाहिए। शहरों को बिजली क्षेत्र की तरह पानी के लिए भी वगीकृत शुल्क प्रणाली (टियर्ड टैरिफ) अपनाना चाहिए, जिसमें खपत बढ़ने के साथ प्रति यूनिट कीमत बढ़ जाती है। इस दिशा में कुछ राज्यों ने प्रगति की है। महाराष्ट्र का राज्य जल संसाधन नियामक प्राधिकरण पानी की कीमत तय करता है, विवादों का समाधान करता है, जो दूसरों के लिए एक मॉडल है।

जलवायु परिवर्तन के लिए हम मनुष्य ही दोषी

भोपाल वर्तमान समय में मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि सुबह ठंड लगती है, दोपहर में तेज गर्मी एवं शाम होने तक बारिश होने लगती है। यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए हम मनुष्य ही दोषी हैं, क्योंकि हमने वनों को काटकर उन्हें समाप्त कर दिया है। प्रकृति ने हर मौसम के लिए चार माह का समय निर्धारित किया है, परन्तु मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए वनों को समाप्त कर प्रकृति के चक्र में अवरोध उत्पन्न किया है। वर्तमान में मौसम का जो स्वरूप है उसके लिए यह आवश्यक है कि हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाकर प्रकृति का पुनः श्रृंगार करें।

राज्यपाल श्री पटेल ने उक्त बातें रविवार को बड़वानी जिले की राजपुर तहसील के ग्राम पंचायत इंदरपुर के ग्राम लोटनदेव में गुजराती चारण समाज न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, परन्तु मनुष्य ने तो सिर्फ लिया ही लिया है। प्रकृति में मनुष्य की हर राशि, नक्षत्र के हिसाब से भी पेड़ निर्धारित हैं। अगर हर व्यक्ति वर्षाकाल में मात्र दो ही पेड़ लगाकर उन्हें बड़ा करे तो जलवायु परिवर्तन की स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है, अन्यथा इसी तरह वनों का दोहन होता रहा तो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन की भयावह स्थिति हमारे समक्ष होगी और हम उसका सामना भी नहीं कर पायेंगे।

राज्यपाल श्री पटेल ने अपने उद्बोधन में बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि परिवार एवं समाज के उत्थान के लिए सभी लोग अपनी बेटियों को अनिवार्य रूप से शिक्षित करें क्योंकि बेटी जब शिक्षित होगी तो वह अपने मायके एवं ससुराल दोनों का नाम रोशन करेगी। शिक्षा के कारण उसकी शादी अच्छे परिवार में होगी, जहां वह अपने बच्चों को भी शिक्षा देकर उनका भी जीवन संवारेगी। शिक्षित माता ही बच्चों में वे सभी संस्कारों को डाल सकती है जो आगे चलकर समाज और देश की उन्नति के लिए आवश्यक है, एक शिक्षित मां 100 शिक्षकों के बराबर है । ग्राम लोटनदेव पहुंचकर महामहिम राज्यपाल श्री पटेल ने सबसे पहले ग्राम में स्थित श्री आवड़ माताजी के मंदिर में पहुंचकर माताजी का पूजन अर्चन कर ग्रामवासियों के सुख एवं समृद्धि की कामना की। साथ ही मंदिर में उनके स्वागत में खड़ी चारण समुदाय की बालिकाओं के सिर पर हाथ रखकर उन्हे आर्शीवाद भी दिया। साथ ही महामहिम राज्यपाल ने मंदिर के समीप ही त्रिवेणी (पीपल, बरगद, नीम) पौधों का भी रोपण किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल श्री पटेल का स्वागत चारण समुदाय की पारंपरिक पगड़ी एवं जैकेट पहनाकर ग्राम के श्री हुकुमनाथा चारण , भूरारामजी चारण, जीवाजी चारण एवं शिवाजी चारण ने किया। इस दौरान ग्राम के सरपंच एवं उप सरपंच ने महामहिम राज्यपाल को स्मृति स्वरूप तीर कमान भी भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान महामहिम राज्यपाल श्री पटेल, चारण समुदाय के अध्यक्ष श्री वल्लभ भाई पटेल एवं श्री हीरालाल पाटीदार ने ग्राम नरावला के शहीद श्री नायक बघेल की धर्मपत्नी श्रीमती संतोषी बघेल को पटेल मोटर्स की तरफ से चेक एवं साड़ी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान महामहिम राज्यपाल श्री पटेल ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाने वाली जिले की कक्षा 12वीं की छात्रा सुश्री राधिका सोनी एवं 10वी की छात्रा लीना यादव को प्रशस्ति पत्र एवं चेक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान महामहिम राज्यपाल श्री पटेल ने अतिथियों के साथ सुशीला देवी उमरावसिंह पटेल सेवा संस्थान खरगोन-बड़वानी के सौजन्य से 2 टीबी मरीजों को प्रतीकात्मक रूप से पोषण आहार का किट का वितरण किया। साथ ही एक सिकलसेल पॉजिटिव बालक को दिव्यांगता प्रमाण पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान चारण समुदाय के अध्यक्ष श्री वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि वे हमेशा से ही अपने क्षेत्र एवं समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्हें हमेशा ही अपने समाज के युवा वर्ग की फिक्र रहती है, उनका हमेशा से ही यही फोकस रहता था कि उनके समाज का युवा कही भटक न जाये। इसे ध्यान में रखते हुए श्री वल्लभ भाई एवं कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री हीरालाल पाटीदार ने मंच से यह घोषणा की, कि 50 करोड़ रुपये की लागत से क्षेत्र में एक विशेष स्वास्थ्य केन्द्र बनेगा जो कि आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से संबद्ध रहेगा। साथ ही समाज के युवा वर्ग के लिए एक स्किल डेवलपमेंट केन्द्र खोला जायेगा। यहाँ पर उन्हें शिक्षित कर एवं हुनर सिखाकर रोजगार भी दिया जायेगा। इन्द्रपुर से लोटनदेव मार्ग निर्माण में भी सरकार को उनके द्वारा विशेष सहयोग दिया जायेगा। लोकसभा सांसद श्री गजेन्द्र सिंह पटेल ने भी कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, पेयजल एवं सड़क हेतु किए जा रहे कार्यों की जानकारी देकर जन समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। साथ ही क्षेत्र में किये जा रहे सिकल सेल एनीमिया एवं टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत किये जा रहे सराहनीय कार्यों का भी जिक्र किया। कार्यक्रम में स्थानीय जन-प्रतिनिधि और ग्रामीणजन उपस्थित थे।

एनजीटी में खुलासा-गंगा बचाने की योजना तैयार, बस हरी झंडी का है इन्तजार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी में बिना ट्रीटमेंट किए सीवेज और औद्योगिक कचरे को गिरने से रोकने के लिए एक कार्ययोजना (एक्शन प्लान) तैयार की है। लेकिन इसे लागू करने से पहले मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण) की मंजूरी जरूरी है। यह जानकारी 23 मई 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वकील ने दी है। इस आधार पर सरकारी वकील ने अदालत से कुछ समय मांगा है ताकि इस योजना को मंजूरी के बाद आधिकारिक रूप से दाखिल किया जा सके। उन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी एनजीटी में पेश किया।

अदालत ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 अगस्त 2025 को होगी। गौरतलब है कि इस मामले में आवेदक राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने एक पत्र याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने वाराणसी में गंगा नदी में घरेलू सीवेज और औद्योगिक कचरे के सीधे प्रवाह की शिकायत की थी। याचिका के साथ उन्होंने कई तस्वीरें भी संलग्न की हैं जिनमें गंगा के विभिन्न तटबंधों पर गंदे पानी का गिरना और तटों पर अतिक्रमण साफ नजर आता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 23 मई 2025 को बड़े पैमाने पर हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पेड़ों को काटे जाने का यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का है। इस मामले में जिन अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है उनमें आगरा जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), आगरा के जिधिकारी, जिला वन अधिकारी और ताज ट्रैपेजियम जोन प्राधिकरण आदि शामिल हैं। आवेदन में फतेहाबाद, सदर, किरावली और आगरा तहसील में पेड़ों के अवैध रूप से काटे जाने का खुलासा किया गया है। साक्ष्य के तौर पर कई अखबारों में छपी खबरें लगाई गई हैं, जिनमें किरावली तहसील में कॉलोनी बनाने के लिए पेड़ों की अवैध कटाई की बात कही गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मई 2025 के आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल से पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी भी पेड़ की कटाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन वर्तमान मामले में ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उद्योग द्वारा अवैध खनन और अमोनियम नाइट्रेट के गलत इस्तेमाल पर सख्त रुख अपनाया है। 23 मई को इस मामले में हुई सुनवाई में एनजीटी ने संबंधित अधिकारियों और खनन कंपनी जय मां चंद्रिका एंटरप्राइजेज को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर मुद्दे को उठाया गया है। एनजीटी ने विस्फोटक नियंत्रक, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महोबा के जिलाधिकारी और खनन कंपनी जय मां चंद्रिका एंटरप्राइजेज को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई एक सितंबर 2025 को होगी। याचिका दाखिल करने वाले अखिलेश कुमार ने आरोप लगाया है कि महोबा जिले की कुलपहाड़ तहसील के लेटा गांव के गट्टा नंबर 576 की 4.5 एकड़ जमीन 24 मई 2001 से 10 वर्षों के लिए खनन के लिए दी गई थी, जिसकी अवधि 2011 में ही समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद जय मां चंद्रिका इंटरप्राइजेज ने अब अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल (एएनएफओ) शेड के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जो अवैध है। अवैध खनन की शिकायत के अलावा, याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि खनन करने वाले को अमोनियम नाइट्रेट की अवैध तरीके से बिक्री की गई और उसका गलत तरीके से उपयोग भी किया गया। याचिकाकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में 30 मार्च 2024 की एक आरटीआई का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूखंड की अनुमति सिर्फ 10 वर्षों के लिए दी गई थी। उन्होंने 25 अप्रैल 2024 की एक अन्य आरटीआई का भी जिक्र किया, जिसमें खनन सुरक्षा महानिदेशालय ने बताया कि गट्टा नंबर 576 में खदान खोलने की कोई सूचना निदेशालय को नहीं दी गई है। एनजीटी ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए सभी पक्षों से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत अब यह जांचेगी कि क्या पर्यावरण और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है।

ढाई हजार से अधिक बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए की श्री महिला गृह उद्योग समिति की सराहना

भोपाल (एजेंसी) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिज्जत पापड़ जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड को स्थापित कर महिला सशक्तिकरण एवं संगठन की शक्ति की मिसाल पेश कर रही बहनों से श्री महिला गृह उद्योग के लिज्जत पापड़ भवन जबलपुर में आत्मीय संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छोटे से गृह उद्योग से देश का प्रतिष्ठित ब्रांड बनने की यात्रा में ढाई हजार से अधिक बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लिज्जत परिवार को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लिज्जत का यह भवन श्रम का मंदिर हैं। इस मंदिर में काम करके आशीर्वाद मिलता हैं। उन्होंने कहा कि श्री महिला गृह उद्योग की बहनों की मेहनत ही लिज्जत के उत्पादों के स्वाद को लाजवाब बनाता हैं। लिज्जत के देश-विदेश में विख्यात होने का कारण भी बहनों की मेहनत हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला, युवा, गरीब एवं किसानों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नरसिंहपुर में हुए किसान उद्योग समागम कार्यक्रम का उल्लेख करते हुऐ बताया कि प्रदेश सरकर किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद-बीज एवं उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने और कृषि उत्पाद को बाजार में बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सरकार और समाज की भागीदारी से महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। आज प्रदेश की अनेक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर परिवार के लालन-पालन और समाज मे अपनी समान भागीदारी निभा रही है और वे समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 31 मई को लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जयंती के अवसर पर ऐसी ही महिलाओं के सम्मान में भोपाल में महिला महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा हैं इसमें प्रधानमंत्री श्री नेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री महिला गृह उद्योग की संचालक श्रीमती प्रज्ञा ओसवाल सहित समिति की बहनों को गृह उद्योग के आगामी उत्पादों एवं योजनाओं के लिए शुभकामनाएं दीं और भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री ने प्रतिकात्मक रूप से समिति की महिला सदस्यों को लाभांश का वितरण किया। उन्होंने गृह उद्योग की पूर्व संचालक श्रीमती पुष्पा बैरी का भी शॉल श्रीफल से सम्मान किया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह, सांसद श्री आशीष दुबे, महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू, विधायक श्री अशोक रोहाणी सहित अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थित रही।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008